राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग
2011–12 की बजट घोषणाओं की स्थिति

पैरा संख्या पार्ट संख्या सब पैरा संख्या	बजट घोषणा	प्रगति
157 0 0	वर्तमान समय में ई–गवेर्नेन्स के बिना गुड गवेर्नेन्स संभव नही है। अतः शासन में सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व को ध्यान में रखते हुए, हमने राज्य सरकार के योजना बजट का 3 प्रतिशत भाग, विभिन्न विभागों को सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग एवं कंप्यूटरोईजेशन पर खर्च करने के निर्देश दिये थे। आगामी वर्ष इस हेतु लगभग 300 करोड़ रूपये को प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व को देखते हुए, इसके लिए धन की कमी नहीं आने दी जायेगी।	सूचनात्मक है
158 0 0	राज्य में इस वर्ष एक नवीन डाटा सेंटर स्थापित किया गया है। राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी के आधारभूत ढांचे को सूदृढ़ करते हुए आगामी वर्ष ब्लॉक एवं जिला स्तर पर लगभग 3 हजार 400 कार्यालयों को राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क से जोड़कर, 120 करोड़ रूपये की लागत से सूचना–तंत्र विकसित किया जायेगा।	राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क हेतु माह अप्रैल 2011 में कार्यादेश जारी कर दिया गया है। माह मई 2012 तक परियोजना का क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित है।
159 0 0	विभिन्न जन सेवायें, जैसे जाति व मूल निवास प्रमाण–पत्र, जन्म–मृत्यु पंजीकरण, लोक सेवा आयोग के आवेदन व प्रवेश पत्र प्राप्त करने, नगर निकायो तथा संस्थाओं के भुगतान इत्यादि की सुविधायें नागरिकों को सुगमता से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, राजस्थान ऑन लाइन परियोजना लागू कि जायेगी, ताकि ई–गवर्नेन्स का वास्तविक लाभ जनता को सुलभ हो सके।	राजस्थान ऑन लाइन परियोजना हेतु विभाग द्वारा विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
160 0 0	इसके अतिरिक्त, State Service Delivery Gateway योजनान्तर्गत 7 विभागों की 42 सेवाओं हेतु घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से आवेदन करने की सुविधा प्रदान की जायेगी।	कार्यादेश जारी कर मैसर्स विप्रो के साथ अनुबन्ध हस्ताक्षरित कर दिया गया है। यह परियोजना सितम्बर 2011 तक क्रियान्वित कर दी जायेगी केन्द्र सरकार द्वारा परियोजना की कुल लागत रूपये 1151 लाख स्वीकृत की गई है। निविदा पश्चात् इस परियोजना हेतु कुल रूपये 150.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता होगी जिसके लिये प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित कर दिये गये है। इस प्रकार

		परियोजना की कुल लागत बढ़कर रूप्ये 1300.25 लाख होगी। इस अतिरिक्त राशि की आवश्यकता वर्ष 2013–14 एवं वर्ष 2014–15 में होगी।
161 0 0	अजमेर और जोधपुर जिलों में पायलट आधार पर ई–डिस्ट्रिक्ट योजना के अंतगर्त जिला कलक्टर कार्यालय से जुडी हुई सेवायें इंटरनेट के माध्यम से नागरिकों को उपलब्ध करवाई जायेंगी।	भारत सरकार द्वारा ई–डिस्ट्रिक परियोजना के अन्तर्गत कुल 642.41 लाख रूपये स्वीकृत किये गये है। परियोजना हेतु लेटर ऑफ इन्टैन्ट मैसर्स एच पी इंडिया लिमिटेड को 01.06.2011 को जारी कर दिया गया है। मूल्यांकन के आधार पर निविदा की लागत 1194.69 लाख रूपये है। तदनुसार वर्ष 2014–15 तक परियोजना हेतु कुल राशि रूपये 1406.51 लाख की आवश्यकता होगी। जिनमें राजकॉम्प के चार्जेज रूपये 56.00 लाख, पीडब्ल्यूसी के रूपये 105.82 लाख और डीईसीएस के रूपये 50.00 लाख सम्मिलित है। इस प्रकार वर्ष 2014–15 तक कुल रूपये 64.10 लाख की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होगी। यह राशि राज्य सरकार द्वारा वहन करने की स्वीकृति प्राप्त हो गई है।